रत्तीराम एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक राज्य पुलिस

आपराधिक अपील संख्या. 2008 का 223

18 अप्रैल, 2013

बेंच: केएस राधाकृष्णन, दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति

<u>भारतीय दण्ड संहिता, 1860 -</u>

धारा 302/149 पीड़ित पर कई आरोपियों द्वारा हमला करने की बात कही गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई- दोषसिद्धि - माना गयाः सबूत स्थापित करते हैं कि पांच आराेपियों ने मृतक पर हमला किया - उनमें से एक की अपील दायर करने से पहले ही मृत्यु हो गई दोषसिद्धि और शेष चार की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी जाती है- जहां तक अन्य आरोपी व्यक्तियों का सवाल है, विरोधाभासी बयान हैं जिससे घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति और मृतक पर हमला करने के संबंध में उचित संदेह पैदा होता है- तदनुसार उन्हें बरी किया जाता है- साक्ष्य – गवाहों के विरोधाभासी बयान

<u>दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -</u>

धारा 157- मजिस्टेट को विशेष रिपोट भेजना - अवधारित गया। जब एफ आइ आर देरी से भेजी जाती है, तो अभियोजन पक्ष की ओर से देरी के लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है- हालांकि , अगर अदालत अभियाेजन संस्करण की सत्यता और विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त है इसके गवाहों के मामले में, एफ आइ आर के प्रेषण में देरी को अभियाेजन पक्ष के मामले के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता है- मौजूदा मामले में, सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि गवाहों का संस्करण विश्वसनीयता का हकदार है।

अपीलकर्ताओ से पर तीन अन्य लोगों के साथ एक 'डी' की मौत का कारण बनने के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन का मामला यह था कि दिनांक 29-09-1995 को रात्रि लगभग 11 बजे

जब पीडब्ल्यू - 5, 6,7 और 12 'डी' के साथ पीडब्ल्यू- 5 के लिए दवा खरीदने के लिए एक दुकान पर थे, सभी आरोपियों ने 'डी' को घेर लिया, उस पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। टायल कोर्ट ने आरोपी 'एम' को आइ पी सी की धारा 148 और 302 के तहत दोषी ठहाराया और शेष आरोपियों को धारा 148 और 302 के साथ 149 आइपीसी के तहत दोषी ठहाराया और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । अपील पर, उच्च न्यायालय ने आराेपी 'जी' को बरी कर दिया और अन्य आरोपियों की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

अभियुक्त 'छ' की उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी। अपीलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया जिसके संदर्भ का उत्तर दिया।

अपीलकर्ताओ के लिए यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि सभी आरोपियों ने मृतक पर हमला किया था, पूरी तरह से सबूतों की गलत विवेचना पर आधारित था, और सीआरपीसी की धारा 157 का अनुपालन न करना आदि ने मुकदमे को दूषित कर दिया।

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने अवधारित करते हुए एक पंक्ति में कहा है कि रिकॉर्ड पर समग्र साक्ष्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आरोपी 'जी' को छोड़कर अन्य सभी आरोपी व्यक्ति मौजूद थे और उन्होंने मिलकर मृतक के साथ मारपीट की। उच्च न्यायालय की सहमति साक्ष्य की किसी भी जांच से रहित है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अध्ययन मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि आरोपी 'छ' ने उकसाया और उसने आरोपी 'ध', 'म', 'बी' और 'जीडी' के साथ मिलकर मृतक पर हमला किया। सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकालने के लिए रिकॉड पर पर्याप्त सबूत हैं कि उन्होंने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था और उन पर हमला करने का सामान्य उददेश्य था। अंततः, हमले में लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उनकी

संलिप्तता के स्पष्ट सबूत हैं और पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-12 ने स्पष्ट रूप से उनके खुले कृत्यों के बारे में बात की हैं। इसलिए अपीलकर्ता 'ध', 'म', 'बी' और 'जीडी' की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है। (पैरा 11, 19 और 22) (1012 जी-एच , -इ 1018-डी)

यह रत्तीराम एवं अन्य बनाम म. प. राज्य पुलिस निरीक्षक आदि के माध्यम से, 2012 (3) एस सी आर 496 , 2012(4) एस सी सी 516 , मोली और अन्य केरल राज्य 2004 (3) एस सी आर, ए आई आर 2004 एस सी 1890 और विद्यायरन बनाम केरल राज्य 2003(5) पूरक एस सी आर 524, (2004) एस सी सी 215 ने म.प. राज्य में निर्णय को नोट नहीं किया। बनाम भूराजी और अन्य। 2001 (2) सप्ल, एस सी आर 128= 2001 ए आइ आर 3372 में अवधारित किया गया है। इस प्रकार , मोली और विद्यायरन प्रति अभियोग है और पुनः परीक्षण के संबंध में उनके विचार को खारिज कर दिया गया है।

1.2. जहां तक अन्य आरोपियों का सवाल हैं, घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी और मृतक पर हमला करने के बारे में भौतिक विरोधाभास हैं। पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-12 के बयानों में स्पष्ट विरोधाभासों से ऐसा लगता है कि उन्होंने अन्य आरोपियों को अपराध में फंसाया है। इस पकार, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य में उनकी संलिप्साबित नहीं होती है। इसलिए, विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण, जिससे उच्च

न्यायालय सहमत है कि सभी आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट की थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। (पैरा 11 और 19) (1013-बी-सी, 1016 - ई -जी)

बालदीन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर 1956,एस सी 181, मसल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1964 एस सी आर 133=ए आई आर 1965 एस सी 202; लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 (1) एस सी आर 130 एस सी सी 437 भार्गवान और अन्य बनाम केरल राज्य 2003 (5) सप्ल. एस सी आर 535=(2004) 12 एससीसी 414; देबाशीष दाठ और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 210(9) एस सी आर 654 (210) 9 एस सी सी 111 अकबर शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2009 (7) एस सी आर 518 (2009) 7 एस सी सी 415 और रामचन्द्रन और अन्य बनाम केरल राज्य 2011 (13) एस सी आर 923 (2011) 9 एस सी सी 257 – संदर्भित।

1.3. सबूतों से पता चलता है कि मृतक कई आपराधिक अपराधों में शामिल था और आरोपी व्यक्तियों और मृतक के बीच कुछ मनमुटाव था। ऐसे में असली हमलावरों के साथ कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाना असामान्य बात नहीं है, (पैरा19) (1017-ए-बी)

1.4. रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की समग्रता के संबंध में, पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू- 12, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के साक्ष्यों को फिल्टर करने

और उसके अध्ययन किए गए मूल्यांकन के आधार पर, यह मानना सुरक्षित नहीं है कि आरोपी - अपीलकर्ता 'आर', 'के', 'आर आर' और ' एस' मौके पर मौजूद थे और इसलिए 149 आई पी सी की सहायता से उनके खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करना अनुचित होगा। क्योंकि घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में उचित संदेह है तदनुसार , वे दोषमुक्त घोषित किए जाते हैं। (पैरा 20-21) (1017-सी-डी, 1018- ई -एफ)

2. सी आर पी सी की धारा 157 का अनुपालन न करने के संबंध में, यह कहना पर्याप्त है कि जब एफ आई आर देरी से भेजी जाती है, तो अभियोजन पक्ष की और से देरी के लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। एफ आई आर की काॅपी मजिस्ट्रेट को भेजने के पीछे मकसद एफ आई आर से जुड़े किसी भी संदेश से बचना है। यदि अदालत अभियोजन पक्ष की बात की सत्यता और गवाहों की विश्वसनीता के संबंध में आश्वस्त है, तो एफ आई आर में देरी को अभियोजन मामले के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता है। यह तथ्यों पर निर्भर करेगा और मामले की परिस्थितियां मौजूदा मामले में, सबूत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि गवाहों का बयान विश्वसनीयता का हकदार है। (पैरा 21) (1017-इ और जी-एच , 1018-ए-सी)

गंगुला अशोक और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य पी. 2000 (1) एस सी आर 2000 एस सी 740- संदर्भित किया गया

निर्णय विधि संदर्भ

2000 (1) एस सी आर 468 पैरा 5 के लिए

2004 (3) एस सी आर 346 पर इंक्यूरियम घोषित किया गया और खारिज कर दिया गया। पैरा 5 के लिए

2003 (5) पूरक एस सी आर 524 पर इंक्यूरियम घोषित किया गया और खारिज कर दिया गया। पैरा 5 के लिए

2001 (2) पूरक एस सी आर 128 पैरा 5 के लिए

2012 (3) एस सी आर 496 पैरा 6 के लिए

ए आई आर 1956 एस सी 181 पैरा 13 के लिए

1964 एस सी आर 133 पैरा 14 के लिए

1989 (1) एस सी आर 130 पैरा 15 के लिए

2003 (5) पूरक एस सी आर 535

पैरा 16 के लिए

2010 (9) एस सी आर 654

पैरा 17 के लिए

2009 (7) एस सी आर 518

पैरा 17 के लिए

2011 (13) एस सी आर 923

पैरा 18 के लिए

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार , आपराधिक अपील संख्या 223/ 2008

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश , जबलपुर 1996 में की आपराधिक अपील संख्या 1568 के निर्णय और आदेश दिनांक 12.03.2007 से।

कि. अ. सं. 2008 का 458

फखरूददिन, राज किशोर चौधरी, सूर्या कमल मिश्रा, अरिशुल चन्दा, टी. महीपाल, अनीस अहमद खान, शोएब अहमद खान अपीलार्थीगण के लिए

विभा दत्ता मखीजा प्रत्यर्थी के लिए

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति,

1. इन दो अपीलों में, 1996 की आपराधिक अपील संख्या 1568 में मध्य प्रदेश के न्यायिक उच्च न्यायालय, जबलपुर की खंडपीठ द्वारा पारित सजा के फैसले और सजा के आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सजा के फैसले पर सहमति व्यक्त की थी। और 1995 के सत्र परीक्षण संख्या 97 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर द्वारा पारित सजा का आदेश, एक गोरेलाल के संबंध में, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संख्या 2 और विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त संख्या 2 के संबंध में, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ताओं को गोरेलाल के साथ धारा 302 के साथ पठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और 1000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

2. तथ्यात्मक स्कोर, जैसा दर्शाया गया है, यह है कि 29.9.1995 को, मृतक ध्रुव उर्फ दौलत, अशोक कुमार, पीडब्लू-5, धीरज, पीडब्लू-6, नरेश, पीडब्लू-7 और लीलाधर, पीडब्लू-12 के साथ लौट रहे थे। सागर जिले के एक गाँव मकरोनिया में "खेर माता" (मंदिर) में आयोजित एक कुश्ती कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रात लगभग 11 बजे घर आया। जैसे ही अशोक कुमार, पीडब्लू-5 ने पेट में दर्द की शिकायत की, वे सभी दवा खरीदने के लिए गोरेलाल की दुकान पर गए और जब वे दुकान पर पहुंचे, तो छोटेलाल के घर से आए सभी आरोपियों ने मृतक दौलत को घेर लिया

और मारपीट शुरू कर दी। साथियों के लाख समझाने-बुझाने के बावजूद आरोपियों ने हमला जारी रखा, जिससे मृतक बेहोश हो गया। जैसे ही अभियोजन की कहानी आगे बढ़ी, उसे अस्पताल ले जाया गया और अंततः उसकी चोटों के कारण मौत हो गई। एफआईआर दर्ज होने पर, आपराधिक कानून लागू किया गया और जांच के बाद अपीलकर्ताओं पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया (संक्षेप में) "अधिनियम"), लेकिन, अंततः, आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 147 , 148 और 302 के तहत आरोप तय किए गए। आरोपी व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष और झूठा फंसाने की दलील दी और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

3. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित करने के लिए 13 गवाहों की जांच की और कई दस्तावेज प्रदर्शित किए। बचाव पक्ष ने कोई सबूत पेश नहीं करने का फैसला किया।

4. विद्वान ट्रायल जज ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी मोहन के खिलाफ आई पी सी की धारा 148 और 302 के तहत और शेष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आई पी सी की धारा 147 और 302 के साथ पठित धारा के तहत आरोप लगाए थे। 149 आई पी सी और धारा 147 आई पी सी के तहत

अलग-अलग सजा देने के अलावा उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जैसा कि यहां पहले बताया गया है।

5. दोषसिद्धि के फैसले से असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ एकल आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी। अपील में, गुण-दोष के आधार पर विभिन्न तर्कों को उठाने के अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि संपूर्ण मुकदमा दूषित हो गया था क्योंकि यह सक्षम अदालत द्वारा मामले को सत्र न्यायालय में सौंपे बिना ही शुरू और समाप्त हो गया था, क्योंकि सत्र न्यायालय सीधे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता था। मामले को सुनवाई के लिए सौंपे बिना अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान। उक्त विवाद को मजबूत करने के लिए गंगुला अशोक और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [1], मोली और अन्य बनाम केरल राज्य [2] और विद्याधरन बनाम केरल राज्य [3] पर भरोसा रखा गया। उच्च न्यायालय ने मप्र राज्य बनाम भूराजी एवं अन्य के फैसले पर भरोसा किया।[4] और इसे एक बाध्यकारी मिसाल माना और दोषसिद्धि को रद्द करने या मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर अपीलों पर कार्रवाई की और निर्णय लिया कि आरोपी गोरेलाल को छोड़कर अन्य सभी आरोपी घटना स्थल पर मौजूद थे और उन्होंने हमले में भाग लिया था और तदनुसार, अन्य आरोपियों के संबंध में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। व्यक्तियों और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संख्या 2 को बरी

कर दिया गया।

6. संपूर्णता के लिए, यह बताना आवश्यक है कि जब मामला दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो यह देखा गया कि इस न्यायालय के निर्णय की दो पंक्तियों के बीच विरोधाभास था और तदनुसार, मामले को संदर्भित किया गया बड़ी बेंच. तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने देखा कि वास्तविक संघर्ष या कलह एक ओर मोली और अन्य (सुप्रा), एक ओर विद्याधरन (सुप्रा) और भूराजी और अन्य के बीच प्रकट हुई थी। (सुप्रा) दूसरी ओर और पुलिस निरीक्षक के माध्यम से रत्तीराम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में उचित विचार-विमर्श के बाद[5], इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया: -

> "66. इन स्पेक्ट्रमों से निर्णय लेने और उपरोक्त परिसरों पर विश्लेषण करने पर, हम अपरिवर्तनीय निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संहिता की धारा 193 के गैर-अनुपालन से संबंधित आपत्ति , जिसके परिणामस्वरूप अंततः अनुसूचित जाति के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा सीधे मनोरंजन और संज्ञान लिया गया। और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989, मुकदमे को ख़राब नहीं करता है और अकेले उक्त आधार पर, दोषसिद्धि को रद्द नहीं किया जा सकता है या फिर से मुकदमा चलाने का निर्देश नहीं दिया

जा सकता है और इसलिए, भूराजी (सुप्रा) में दिया गया निर्णय) सही कानून का निर्धारण करता है, क्योंकि न्याय में कोई विफलता नहीं होती है या अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है।67. मोली (सुप्रा) और विद्याधरन (सुप्रा) में दिए गए निर्णयों में भूराजी (सुप्रा) में दिए गए निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है, जो एक बाध्यकारी मिसाल है, और इसलिए वे पर इन्क्यूरियम हैं और इसके अलावा, इसमें निर्धारित कानून है, जिसके तहत दोषसिद्धि निर्धारित की जाती है। एक तरफ या मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए दोषसिद्धि को रद्द करने के बाद भेज दिया जाता है, यह कानून के सही प्रस्ताव को उजागर नहीं करता है और, तदनुसार, उन्हें इस हद तक, खारिज कर दिया जाता है।

7. चूंकि उक्त स्कोर पर विवाद को शांत कर दिया गया है, इसलिए हमें वर्तमान में अपील की योग्यताओं पर विचार करना आवश्यक है। इस समय, हम यह कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील में निर्णय सुनाए जाने के बाद छोटेलाल की मृत्यु हो गई और बाबूलाल की मृत्यु इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान हो गई है और इसलिए, जहाँ तक बाबूलाल का सवाल है, अपील निरस्त की जाती है।

8. 2008 की आपराधिक अपील संख्या 223 में अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री फखरुद्दीन ने तर्क दिया है कि विचरण न्यायालय का यह निष्कर्ष जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने हमला किया था, बिल्कुल सबूतों की गलत विवेचना पर आधारित है। , क्योंकि उनमें किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य में शामिल होने के लिए कुछ भी नहीं है। यह उनकी वैकल्पिक दलील है कि सभी आरोपी घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और इसलिए, यहां सभी अपीलकर्ताओं की आई पी सी की धारा 149 के तहत सजा पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है।

9. 2008 की आपराधिक अपील संख्या 458 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अनीस अहमद खान ने प्रस्तुत किया है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है और रिपोर्ट की आगे की प्रति मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई है जैसा कि संहिता की धारा 157 के अधीन आवश्यक है। और, इसलिए, मुकदमा दूषित हो गया है। उनका यह भी कहना है कि पिछली दुश्मनी के कारण मुखबिर ने कई लोगों को फंसाने की कोशिश की है, हालांकि अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और इसलिए, वे बरी किए जाने के पात्र हैं।

10. इसके विपरीत, राज्य की विद्वान वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा का तर्क है कि हमले में सभी आरोपी व्यक्तियों को शामिल करने के सबूत हैं और यहां तक कि यह मानते हुए कि उनके लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं

किया गया है, वे हमले के सामान्य उद्देश्य से अवगत होकर गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे और इसलिए, आईपीसी की धारा 149 के तहत दोषसिद्धि में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. सबसे पहले, हम इस मुद्दे पर ध्यान देंगे कि क्या सभी आरोपी व्यक्तियों ने हमले में भाग लिया था या नहीं। विदित हो कि, विद्वान ट्रायल जज के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी इस बात पर विचार किया है कि एक्स पी-7, एफआईआर और पीडब्लू-5, अशोक कुमार और पीडब्लू-12, लीलाधर की गवाही पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने मृतक के साथ मारपीट की थी। एफआईआर के अवलोकन से पता चला कि रमेश, कन्छेदी, बाबूलाल, रामचरण और रत्तीराम पर आरोप है कि वे लोग लाठी-डंडे लेकर मृतक के साथ मारपीट करने आये थे। प्राथमिकी में इस बात का जिक्र है कि कनछेदी कुर्मी ने मृतक को पत्थर के बड़े टुकड़े से और रामचरण कुर्मी ने लाठी से मारा. आरोपी बाबूलाल, रत्तीराम, सत्यनारायण व रमेश ने लात-घूंसों से मारपीट की। प्राथमिकी में यह उल्लेख किया गया है कि छोटेलाल ने मृतक को मारने के लिए उकसाया और धनीराम कुर्मी, गोवर्धन कुर्मी, बद्री कुर्मी और मोहन कुर्मी ने हमला किया और विशिष्ट कृत्यों को उनके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अशोक कुमार, पीडब्लू-5 ने मुख्य परीक्षण में बताया कि धनीराम ने दौलत के सिर पर डंडे से वार किया, मोहन ने तलवार से सिर पर वार किया और बद्री और गोवर्धन ने उसकी पीठ और हाथ पर वार

किया। इसके बाद, वह गवाही देने के लिए आगे बढ़े कि बाकी आरोपियों ने मुक्कों और लातों से मारपीट की। एफआईआर दर्ज कराने वाले इस गवाह ने जिरह में कहा है कि आरोपी छोटेलाल, कंछेदी, रामचरन, रमेश और गोरेलाल के पास लाठी नहीं थी। अतः उन्होंने यह नहीं बताया है कि कनछेदी ने किसी बड़े पत्थर से प्रहार किया है। लीलाधर, पीडब्लू-12 ने छोटेलाल द्वारा दिए गए उपदेश और धनीराम और मोहन द्वारा दिए गए प्रहारों के बारे में बताया है। जहां तक छोटेलाल, बाबूलाल, सत्यनारायण, रत्तीराम और गोरेलाल का सवाल है, उनका कहना है कि उन्होंने मृतक को पैरों और भिंची हुई मुट्ठियों से मारा। जिरह में उन्होंने बताया कि बाबूलाल घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा है कि दौलत को पैरों पर कोई लाठी नहीं लगी। उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ लोग निहत्थे थे. धीरज, पीडब्लू-6, और नरेश, पीडब्लू-7, जिन्हें चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था, मुकर गए हैं। विद्वान ट्रायल न्यायाधीश, जैसा कि फैसले से स्पष्ट है, इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सशस्त्र थे और उन्होंने मृतक पर हमला किया था। उच्च न्यायालय ने एक पंक्ति में कहा है कि रिकॉर्ड पर समग्र साक्ष्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गोरेलाल को छोड़कर अन्य सभी आरोपी मौजूद थे और उन्होंने मिलकर मृतक के साथ मारपीट की। उच्च न्यायालय की सहमति, हम सम्मानपूर्वक कह सकते हैं, साक्ष्य की किसी भी जांच से रहित है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अध्ययन

मूल्यांकन पर, हमारा मानना है कि छोटेलाल ने उकसाया और उसने धनीराम, मोहन, बद्री और गोवर्धन के साथ मिलकर मृतक के साथ मारपीट की। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनकी संलिप्तता के स्पष्ट सबूत हैं और पीडब्लू-5 और पीडब्लू-12 ने स्पष्ट रूप से उनके खुले कृत्यों के बारे में बात की है, जबकि जहां तक दूसरों का सवाल है, उनके द्वारा मृतक पर हमला करने के बारे में भौतिक विरोधाभास हैं। इस प्रकार, किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य में उनकी संलिप्तता अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं की गई है और इसलिए, हम विद्वान ट्रायल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जिससे उच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने मृतक के साथ मारपीट की थी।

12. प्रस्तुतीकरण का अगला अंग आईपीसी की धारा 149 की सहायता से सभी आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि की औचित्यता से संबंधित है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने माना है कि सभी आरोपी व्यक्ति मौजूद थे और उन्होंने मृतक के साथ मारपीट की थी। हाईकोर्ट ने राय दी कि अपीलकर्ता गोरेलाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राज्य की विद्वान वकील सुश्री मखीजा का तर्क है कि इस बात की पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी-अपीलकर्ता घटना स्थल पर मौजूद थे और उनका सामान्य उद्देश्य तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट है कि उन्होंने मृतक पर हमला करने के लिए सामान्य उद्देश्य साझा किया था और उन्हें किये जाने वाले कृत्य की जानकारी थी। इसे विस्तार से बताते हुए, उन्होंने आग्रह किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां आरोपी व्यक्ति केवल दर्शक थे, बल्कि वास्तव में, अन्य लोगों को यह पता था कि कुछ आरोपी लाठियां ले जा रहे थे और मोहन तलवार ले जा रहा था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री फखरुद्दीन और श्री अनीस अहमद खान, इसके विपरीत, दृढ़तापूर्वक आग्रह करेंगे कि अभियोजन पक्ष वास्तव में यह साबित नहीं कर सका है, हमले में शामिल लोगों को छोड़कर, कि अन्य आरोपी व्यक्ति वास्तव में उपस्थित थे और आगे भी यह मानते हुए कि वे मौजूद थे, उनकी मात्र उपस्थिति आईपीसी की धारा 149 के तहत दी गई सामान्य वस्तु की अवधारणा को आकर्षित नहीं करेगी।

13. इससे पहले कि हम इस संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ें, हम आईपीसी की धारा 149 की आकर्षकता से संबंधित कुछ घोषणाओं का उल्लेख करना उचित समझते हैं। बालादीन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [6] में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार राय दी है: -

> "यह अच्छी तरह से तय है कि किसी सभा में मात्र उपस्थिति ऐसे व्यक्ति को गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं बनाती है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि उसने कुछ किया है या ऐसा कुछ करने से चूक गया है जो उसे गैरकानूनी सभा का सदस्य बना देगा, या जब तक मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 142 के अंतर्गत आता है ।

14. उपरोक्त मामले में दिए गए आदेश पर मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [7] मामले में चार न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया था , जिसमें पीठ ने बालादीन (सुप्रा) के मामले में की गई टिप्पणियों को इस आधार पर अलग किया था कि उक्त निर्णय को उस मामले के विशेष तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और इसे कानून के अयोग्य प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है। चार जजों की बेंच ने उक्त निर्णय की व्याख्या करने के बाद निम्नानुसार व्यवस्था दी: -

> "यह कहना सही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी

सभा का सदस्य ठहराए जाने से पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि उसने कुछ अवैध प्रत्यक्ष कार्य किया है या सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कुछ अवैध चूक का दोषी है। सभा। वास्तव में, धारा 149 यह स्पष्ट करती है कि यदि किसी गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है, या उस सभा के सदस्यों को पता था कि अभियोजन में अपराध किए जाने की संभावना है। वह वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध को करने के समय, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है; और यह सशक्त रूप से इस सिद्धांत को सामने लाता है कि धारा 149 द्वारा निर्धारित सजा एक अर्थ में प्रतिगामी है और हमेशा इस आधार पर आगे नहीं बढ़ती है कि अपराध वास्तव में गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया है।

15. लालजी बनाम यूपी राज्य में यह देखा गया है कि गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य सभा की प्रकृति, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और घटना स्थल पर या उससे पहले सभा के व्यवहार से पता लगाया जा सकता है। . यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाने वाला एक अनुमान है।

16. भार्गवन और अन्य बनाम केरल राज्य[मामले में यह माना गया है कि इसे कानून के सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कृत्य साबित नहीं हो जाता, जिस पर गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप है। , यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी सभा का सदस्य है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे यह समझना चाहिए कि सभा गैरकानूनी थी और आईपीसी की धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कार्य को करने की संभावना थी। बेंच ने "ऑब्जेक्ट" शब्द पर जोर दिया और कहा कि इसका मतलब उद्देश्य या डिजाइन है और इसे "सामान्य" बनाने के लिए इसे सभी द्वारा साझा किया जाना चाहिए।

17. देबाशीष दाऊ और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में , इस न्यायालय ने अकबर शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [11] के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी प्रकृति के मामले में अभियोजन की आवश्यकता है यह स्थापित करने के लिए कि क्या आरोपी व्यक्ति मौजूद थे और क्या उन्होंने एक समान वस्तु साझा की थी।

18. रामचन्द्रन और अन्य बनाम केरल राज्य [12] में, इस न्यायालय ने इस प्रकार राय दी है: -

> "27. इस प्रकार, यह न्यायालय निर्णयों की श्रृंखला में बहुत सतर्क रहा है कि जहां बड़ी संख्या में व्यक्तियों के खिलाफ

सामान्य आरोप लगाए गए हैं, अदालत स्पष्ट रूप से सबूतों की जांच करेगी और यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य अस्पष्ट है, तो बड़ी संख्या में व्यक्तियों को दोषी ठहराने में संकोच करेगी। अदालत के लिए यह जांच करना अनिवार्य है कि यदि किया गया अपराध सामान्य उद्देश्य के सीधे अभियोजन में नहीं है, तो भी यह आईपीसी की धारा 149 के दूसरे भाग के तहत आ सकता है, यदि अपराध ऐसा था जैसा सदस्यों को पता था कि इसकी संभावना थी प्रतिबद्ध होना करने के लिए। आगे यह निष्कर्ष निकालना होगा कि व्यक्तियों की संख्या क्या थी; उनमें से कितने केवल निष्क्रिय गवाह थे; उनके अस्त्र-शस्त्र क्या थे. चोटों की संख्या और प्रकृति पर भी विचार करना प्रासंगिक है। घटना के समय "सामान्य वस्तु" भी विकसित हो सकती है।

19. उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमें यह देखना होगा कि घटना के समय सभी अपीलकर्ता उपस्थित थे या नहीं। हम पहले ही राय दे चुके हैं कि छोटेलाल ने उकसाया था और अन्य आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् धनीराम, मोहन, बद्री और गोवर्धन ने मृतक के साथ मारपीट की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि उन्होंने एक गैरकानूनी सभा बनाई थी और मृतक पर हमला करने का सामान्य उद्देश्य था। जिसने अंततः हमले में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। जहां तक

अन्य आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् बाबूलाल, सत्यनारायण, रत्तीराम, कनछेदी, रामचरण और रमेश का सवाल है, आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में वास्तव में विरोधाभासी बयान हैं क्योंकि पीडब्लू-12 ने कहा है कि बाबूलाल उपस्थित नहीं थे। घटना का स्थान. अशोक कुमार, पीडब्लू-5, ने कनछेदी, रामचरण, रमेश और गोरेलाल द्वारा रखे गए हथियारों के बारे में खुद का खंडन किया है। लीलाधर, पीडब्लू-12, ने रमेश और गोवर्धन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। पीडब्लू-5 और पीडब्लू-12 के बयानों से स्पष्ट विरोधाभासों से ऐसा लगता है कि उन्होंने बाबूलाल, सत्यनारायण, रत्तीराम, रमेश और रामचरण को अपराध में फंसाया है। जहां तक गोवर्धन का सवाल है, पीडब्लू-5 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने और बद्री ने दौलत की पीठ और गर्दन पर लाठियों से वार किया। चिकित्सीय साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं। पीडब्लू-5 की जिरह में उसकी गवाही को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। अ0सा0-13 के साक्ष्य में यह बात सामने आयी है कि अ0सा0-5 बाबूलाल, कनछेदी तथा उसके भाई के साथ जा रहा था। हम इसका जिक्र केवल यह उजागर करने के लिए कर रहे हैं कि कई लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया है। सबूतों से पता चलता है कि मृतक कई आपराधिक अपराधों में शामिल था और आरोपी व्यक्तियों और मृतक के बीच कुछ मनमुटाव था। ऐसे में असली हमलावरों के साथ कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाना असामान्य बात नहीं है।

20. रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की समग्रता के संबंध में, पीडब्लू-5

और पीडब्लू-12 के साक्ष्यों को फ़िल्टर करने और अध्ययन किए गए मूल्यांकन के आधार पर हमारी सुविचारित राय है कि यह मानना सुरक्षित नहीं है कि आरोपी- अपीलकर्ता रमेश, कनछेदी, रत्तीराम और सत्यनारायण घटनास्थल पर मौजूद थे और इसलिए, धारा 149 आई पी सी की सहायता में दोषसिद्धि दर्ज करना अनुचित होगा और हम ऐसा सोचने के इच्छुक हैं क्योंकि हमें घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में उचित संदेह है।

21. यदि हम श्री खान की इस दलील पर ध्यान नहीं देते हैं कि जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 का पूरी तरह से गैर-अनुपालन हुआ है, तो मुकदमा दुषित हो गया है, तो हम अपने कर्तव्य में विफल होंगे। विद्वान ट्रायल कोर्ट के फैसले पर गौर करने पर हमने देखा कि हालांकि इस तरह का रुख विद्वान ट्रायल जज के समक्ष कमजोर ढंग से उठाया गया था, लेकिन जिरह में इस संबंध में जांच अधिकारी से कोई सवाल नहीं पूछा गया था। विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने उसी पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर गवाही की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए राय दी है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि एफआईआर, एक्स पी-7, पूर्व दिनांकित या अलंकृत था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा कोई विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में गलती नहीं पाई जा सकती है। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि जब एफआईआर देरी से

भेजी जाती है, तो अभियोजन पक्ष की ओर से देरी के लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। हम आगे बता सकते हैं कि एफआईआर की एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजने के पीछे का उद्देश्य एफआईआर से जुड़े किसी भी प्रकार के संदेह से बचना है। इस तरह का संदेह अदालत को यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए मजबूर कर सकता है कि एफआईआर पूर्व-समय या पूर्व-दिनांकित होने की संभावना थी। अदालत अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है। हालाँकि, यदि अदालत अभियोजन पक्ष की बात की सत्यता और गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में आश्वस्त है, तो इसे अभियोजन मामले के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता है। यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मौजूदा मामले में, गहनता से विचार करने पर साक्ष्यों की विस्तृत जांच करने पर, हमने पाया कि साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि गवाहों का बयान विश्वसनीयता का पात्र है, जैसा कि पहले विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार, श्री खान द्वारा की गई यह भारी शिकायत महत्वहीन हो जाती है और प्रस्तुतीकरण खारिज कर दिया जाता है।

22. परिणामस्वरूप, हम अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ताओं, अर्थात् धनीराम, मोहन, बद्री और गोवर्धन के खिलाफ दर्ज सजा के फैसले और सजा के आदेश की पुष्टि करते हैं। अभियुक्त मोहन को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433ए के तहत कारावास में चौदह वर्ष की सजा पूरी करने के बाद छूट का लाभ मिलने पर रिहा कर दिया गया

है। जहां तक धनीराम का सवाल है, वह हिरासत में है। आरोपी-अपीलकर्ता बद्री और गोवर्धन जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया है।' अभियुक्त-अपीलकर्ताओं, सत्यनारायण, रमेश, कनछेदी और रत्तीराम को बरी कर दिया जाता है और चूंकि वे जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें उनके जमानत बांड से मुक्त कर दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सत्य प्रकाश बैरागी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।